



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 6 जुलाई, 1998/15 आषाढ़, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 6 जुलाई, 1998

संख्या 1-56/98-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं काय संचालन नियमावली, 1997 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 1998 (1998 का विधेयक

संख्यांक 3) जो दिनांक 6-7-1998 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

अजय भण्डारी,
सचिव।

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 1998

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 (1972 का 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, संक्षिप्त नाम 1998 है। और प्रारम्भ।

(2) यह 1 अप्रैल, 1998 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 की धारा 3 में:—

धारा 3 का संशोधन।

1972 का 9

- (i) खण्ड (क) में, “छः सौ” शब्दों के स्थान पर, “नौ सौ” शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) खण्ड (ख) में, “चार सौ” शब्दों के स्थान पर, “छः सौ” शब्द रखे जाएंगे; और
- (iii) प्रथम परन्तुक के पैरा (i) और (ii) में, “दो सौ” और “चालीस” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “तीन सौ” और “साठ” शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 की धारा 3 का संशोधन वर्ष 1994 में किया गया था जो उन बच्चों के माता-पिता को, जिन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन 26 अक्टूबर, 1962 और 3 दिसम्बर, 1971 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपात के दौरान सशस्त्र बल में सेवा की है, छः सौ रुपये प्रति वर्ष के मूल्य की युद्ध जागीर देने और उन बच्चों के माता-पिता, जो द्वितीय महायुद्ध के दौरान हिज मैजिस्ट्री के वल में भर्ती किए गए थे या कमीशनड किए गए थे, चार सौ रुपये प्रति वर्ष के मूल्य की युद्ध जागीर देने का उपबन्ध करता है। जहां तीन से अधिक बच्चों ने सेवा की है या सेवा कर रहे हैं पूर्व कथित की दशा में दो सौ रुपये प्रति वर्ष और पश्चात् कथित की दशा में चालीस रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त रकम, ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त बच्चे के लिए संदत्त की जाएगी।

तब से कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसलिए यह युक्तियुक्त समझा गया है कि प्रथम अप्रैल, 1998 से युद्ध जागीरों की रकम को छः सौ, चार सौ, दो सौ और चालीस रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर क्रमशः नौ सौ, छः सौ, तीन सौ और साठ रुपये कर दिया जाए।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

शिमला :
6-7-1998

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2, हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1972 के अधीन संदेय नकद युद्ध जागीर पुरस्कार की रकमों को छः सौ, चार सौ, दो सौ और चालीस रुपये प्रति वर्ष से क्रमशः नौ सौ, छः सौ, तीन सौ और साठ रुपये प्रति वर्ष तक बढ़ाने का उपबन्ध करता है। प्रस्तावित परिवर्तन के कारण प्राक्कलित व्यय का आक्कलन नहीं किया जा सकता क्योंकि पूर्वोक्त अनुदान के लिए आवेदकों की संख्या समय-समय पर बदलती रहती है। तथापि यदि आवेदकों की वर्तमान संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो राजकोष में लगभग 14 लाख, 78 हजार, 4 सौ, 20 रुपये का अतिरिक्त व्यय अन्तर्वर्तित होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[सा० प्रश्ना० वि० नस्ति संख्या जी० ए० डी० ई० (एफ०) 1-2/98]

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश युद्ध पुरस्कार (संशोधन) विधेयक, 1998 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती है।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 3 of 1998

**THE HIMACHAL PRADESH WAR AWARDS (AMENDMENT)
BILL, 1998**

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972 (Act No. 9 of 1972).

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows :—

(1) This Act may be called the Himachal Pradesh War Awards (Amendment) Act, 1998.

Short title
and comm-
encement.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of April, 1998.

(9 of 1972)

2. In section 3 of the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972,—

Amendment
of section
3.

- (i) in clause (a), for the words “six hundred”, the words “nine hundred” shall be substituted;
- (ii) in clause (b), for the words “four hundred”, the words “six hundred” shall be substituted; and
- (iii) in paras (i) and (ii) of the first proviso, for the words “two hundred” and “forty”, the words “three hundred” and “sixty” respectively shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 3 of the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972 was amended in the year, 1994, which provides for the grant of War Jagirs of the value of Rs. 600/- per annum to the parents of such children who have served in the Armed Forces during the National Emergency declared by the President of India under Article 352 of the Constitution on 26th October, 1962 and 3rd December, 1971 and for the grant of War Jagir of the value of Rs. 400 per annum to the parents of such children who were enrolled or commissioned for service in His Majesty's Forces during the Second World War. In case where more than three children have served or are serving, an additional amount of Rs. 200/- per annum in case of former and Rs. 40/- per annum in case of latter is to be paid for every such additional child.

Since then, there has been steep rise in prices. It has, therefore, been considered reasonable that the amount of War Jagir are increased from Rs. 600/-, Rs. 400/-, Rs. 200/- and Rs. 40/- per annum to Rs. 900/-, Rs. 600/-, Rs. 300/- and Rs. 60/- per annum respectively with effect from 1st April, 1998.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

SHIMLA :

The 6-7-1998.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill seeks to make the provisions for the increase of the amounts of the cash War Jagir Awards payable under the Himachal Pradesh War Awards Act, 1972 from Rs. 600/-, Rs. 400/-, Rs. 200/-, and Rs. 40/- per annum to Rs. 900/-, Rs. 600/-, Rs. 300/- and Rs. 60/- per annum respectively. The estimated expenditure due to proposed change can not be assessed as the number of the applicants for the aforesaid grant continues to vary from time to time. However, if there is no increase in the present number of applicants, the additional expenditure involved would be Rs. 14,78,420/- per annum approximately to the State ex-chequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-NIL-

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[GAD FILE NO. GAD-E (F) 1-2/98]

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh War Awards (Amendment) Bill, 1998 recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.